

इस दौरान रक्षा मंत्री, गृह मंत्री और संसदीय कार्य मंत्री को लगातार आपत्ति के बीच राहुल गांधी ने सरकार को घेरा और कहा कि आखिर सरकार किस बात से घबरा रही है। राहुल गांधी ने अपने बयान में बोला, ये डरे हुए हैं, मुझे कोलन नहीं दे रहे। मुझे समझ नहीं आ रहा कि कदते हैं कि ये आतंकवाद से लड़ते हैं लेकिन एक कोट से डरते हैं। इसमें ऐसा क्यों है जो डरना उठा रहे हैं। धन्य रहे हैं। ये डरे नहीं हैं तो मुझे कोलन दें। वे डर क्यों

भटेरा रेलवे ओवरब्रिज की डेडलाईन पर संकट, फिर आगे बढ़ने के आसार

8 फरवरी के बाद मुआवजा मिलेगा, मवन हटाने में लगेगा लंबा वक्त

सिटी रिपोर्टर।

पद्मेश न्यूज। बालाघाट।

शहर के सबसे व्यस्त और प्रमुख मार्गों में शामिल भटेरा रोड पर प्रस्तावित ओवरब्रिज का निर्माण वर्षों बाद भी गति नहीं पकड़ सका है। ओवरब्रिज का भूमिपूजन हुए लंबा समय बीत चुका है, लेकिन जमीनी हकीकत यह है कि अब तक केवल गिने-चुने प्लटर ही खड़े हो पाए हैं। निर्माण कार्य की धीमी रफ्तार से आम नागरिकों में नाराजगी बढ़ती जा रही है, यालाथा व्यवस्था पर भी इसका सीधा असर पड़ रहा है। अब प्रशासन ने नियमानुसार 8 जनवरी को अधिसूचना का प्रकाशन किया है। इस अधिसूचना की समय-सीमा 8 फरवरी को समाप्त हो रही है। प्रशासनिक अधिकारियों का कहना है कि निर्धारित अवधि पूरी होने के बाद अगली प्रक्रिया शुरू की जाएगी। इस संबंध में एसडीएम ने जानकारी देते हुए बताया कि 8 फरवरी के बाद चिन्हित भवनों और दुकानों के प्रभावित लोगों को मुआवजा वितरण की प्रक्रिया प्रारंभ की जाएगी। मुआवजा वितरण के बाद ही भवन हटाने की कार्यवाही संपन्न हो सकेगी, जिससे ओवरब्रिज निर्माण को आगे बढ़ाने का रास्ता साफ होगा। शहर के प्रमुख और अत्यंत व्यस्त भटेरा मार्ग पर निर्माणप्रधानी देखते ओवरब्रिज की प्रगति लगातार सख्तियों के घेरे में बनी हुई है। प्रशासनिक प्रक्रियाओं में तो रही देरी, खबरसंसार में काब अतः तैयार न होना और भू-अर्जन से जुड़ी जटिलताओं के कारण यह परियोजना निर्धारित समय-सीमा में पूरी होती नजर नहीं आ रही है। एसडीएम उपमण्डल सोनी ने जानकारी देते हुए बताया कि भटेरा ओवरब्रिज



निर्माण के लिए प्रभावित भवनों और दुकानों को लेकर 8 जनवरी को भू-अर्जन अधिनियम की धारा 19 के तहत ओवरब्रिज का प्रकाशन किया गया है। इसके लिए नियमानुसार 30 दिनों की आपति अवधि दी गई है, जो आगामी 8 फरवरी को समाप्त हो रही है। अवधि समाप्त होने के बाद चिन्हित भवनों और दुकान मालिकों को मुआवजा वितरण की प्रक्रिया शुरू की जाएगी। मुआवजा मिलने के पश्चात ही भवनों और दुकानों

को हटाने की कार्यवाही आगे बढ़ाई जा सकेगी। भटेरा मार्ग पर लगभग 38 करोड़ रुपये की लागत से रेलवे ओवरब्रिज का निर्माण किया जा रहा है। इस ओवरब्रिज को अक्टूबर 2026 तक पूर्ण किया जाना था, लेकिन जिस तरह से प्रशासनिक स्तर पर प्रक्रियाएं लंबित हैं और वैकल्पिक खयबस्तन मार्ग अब तक तैयार नहीं हो सका है, उससे यह स्पष्ट होता जा रहा है कि परियोजना तथा समय में पूरी होना मुश्किल है। ओवरब्रिज की प्रस्तावित

लंबाई करीब 1313 मीटर और चौड़ाई लगभग 8.4 मीटर निर्धारित की गई है। रेलवे लाइन के ऊपर बनने वाले हिस्से को छोड़कर शेष निर्माण कार्य राज्य सरकार की सेतु एजेंसी द्वारा किया जाना है, जिसके तहत कुल 42 प्लटर बनाए जाने हैं। अब तक केवल गिने-चुने प्लटरों का ही निर्माण हो सका है, जिससे कार्य की धीमी गति साफ झलकती है। प्रशासनिक सूत्रों के अनुसार, ओवरब्रिज की लंबाई और चौड़ाई की जद में आने वाले भावासीय और व्यावसायिक भूखंडों के भू-अर्जन का मुआवजा अभी तक वितरित नहीं किया गया है। मुआवजा वितरण के बाद ही भवनों और दुकानों को तोड़ने की प्रक्रिया शुरू होगी, जिसमें स्वाभाविक रूप से लंबा समय लगने की संभावना है। वर्ष 2025 में राज्य विभाग और लोक निर्माण विभाग द्वारा संयुक्त रूप से सर्वे किया गया था। इस सर्वे में ओवरब्रिज निर्माण से प्रभावित कुल 224 मकान और दुकानें चिन्हित की गई थीं। भू-अर्जन सर्वे के बाद ई-पोर्टलैंड सीमेंट और एम्पोजीआरडीसी द्वारा इन संपत्तियों का मूल्यांकन किया गया, जिसमें कुल मुआवजा राशि लगभग 35 करोड़ रुपये आंकी गई है। फिलहाल भटेरा मार्ग पर रोजाना लगने वाले जाम और अप्रुपे निर्माण के कारण आम नागरिकों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। अब सभी की निगाहें 8 फरवरी के बाद शुरू होने वाली मुआवजा वितरण प्रक्रिया और उसके बाद होने वाली कार्यवाही पर टिकी हैं, जिससे यह तय होगा कि भटेरा रेलवे ओवरब्रिज का निर्माण कब रफ्तार पकड़ पाएगा।

दहेज प्रताड़ना से तंग युवती ने पति, सास-ससुर पर दर्ज कराई रिपोर्ट

पद्मेश न्यूज। बालाघाट। दहेज की मांग को लेकर शारीरिक व मानसिक प्रताड़ना, मारपीट तथा जान की धमकी देने का गंभीर मामला सामने आया है। खैरलांजी थाना क्षेत्र की रहने वाली 23 वर्षीय युवती ने अपने पति, सास और ससुर के विरुद्ध दहेज प्रताड़ना की रिपोर्ट दर्ज कराई है। पुलिस ने आरोपियों को खिलाफ भारतीय न्याय संहिता एवं दहेज प्रतिबंध अधिनियम की विभिन्न धाराओं के तहत अपराध पंजीबद्ध कर जांच प्रारंभ कर दी है। प्राप्त जानकारी के अनुसार पौडीठा का मायका खैरलांजी थाना क्षेत्र में स्थित है। उसका विवाह 23 अप्रैल 2024 को सामाजिक रीति रिवाज से ग्राम लोधी टोला, बहलौल तिरौड़ा जिला गोंदिया (महाराष्ट्र) निवासी राजकुमार लिहारे के साथ हुआ था। विवाह के समय युवती के माता-पिता ने अपनी सामर्थ्य अनुसार दहेज दिया था। पौडीठा का पति खैरी किसानों का कार्य करता है। शादी के लगभग एक माह तक ससुराल पक्ष का व्यवहार सामान्य रहा लेकिन इसके बाद पति राजकुमार लिहारे यह कहकर प्रताड़ित करने लगा कि उसे पत्नी पसंद नहीं है और उसके मायके वाली ने शादी में कम सामान दिया है तथा मोटरसाइकिल भी नहीं दी। इसी बात को लेकर वह मारपीट करने लगा। जब पौडीठा ने इसकी शिकायत अपनी सास इंटाबाई लिहारे और ससुरा सुंदरलाल लिहारे से की तो उन्होंने भी दहेज कम लाने का ताना देते हुए गाली गलौज शुरू कर दी। दहेज की मांग और प्रताड़ना से परेशान होकर युवती ने अपने पिता को फोन कर जानकारी दी। पिता ने ससुराल पहुँचकर पति एवं सास-ससुर को समझाशुन दी। जिसके बाद कुछ समय तक हालात सामान्य रहे। किंतु कुछ महीनों बाद पुनः तीनों द्वारा शारीरिक एवं मानसिक रूप से प्रताड़ित किया जाने लगा। 24 दिसंबर 2025 को राजकुमार लिहारे ने युवती पर किसी अन्य व्यक्ति से संबंध होने का आरोप लगाते हुए चरित्र पर शक की शिकायत मारपीट की और घर से निकाल दिया। साथ ही यह धमकी दी कि यदि वह दोबारा घर लौटी तो उसे जान से मार दिया जाएगा। इसके बाद युवती अपने पति को खुलाका मायके आ गई। 29 जनवरी को दोपहर करीब 12 बजे पति राजकुमार लिहारे अपनी माँ इंटाबाई लिहारे और पिता सुंदरलाल लिहारे के साथ पौडीठा के मायके पहुंचे और मोटरसाइकिल, सोनी के चैन तथा 50 हजार रुपये नकद दहेज की मांग की। उन्होंने कहा कि जब तक वह सामान लेकर नहीं आने देंगे, उसे ससुराल में प्रवेश नहीं दिया जाएगा, और निमा सामान के अति पर जान से खत्म कर देने की धमकी दी। इसके बाद तीनों झाड़ा-विवाद कर वहाँ से चले गए। युवती लंबे समय तक इस आशय में चुप रही कि ससुराल पक्ष के व्यवहार में सुधार होगा, लेकिन जब किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं हुआ तो भमबन्धन 1 फरवरी को खैरलांजी थाना पहुँचकर शिकायत दर्ज कराई। खैरलांजी पुलिस ने पौडीठा की रिपोर्ट पर उसके पति राजकुमार लिहारे, सास इंटाबाई लिहारे एवं ससुर सुंदरलाल लिहारे के विरुद्ध दहेज की मांग को लेकर प्रताड़ना, मारपीट एवं जान से मारने की धमकी देने के आरोप में मामला दर्ज कर लिया है। पुलिस द्वारा मामले की विवेचना की जा रही है।

कैरियर हायर सेकेण्डरी स्कूल में १२वीं के छात्रों को दी गई बिदाई

पद्मेश न्यूज। बालाघाट। स्थानीय कैरियर हायर सेकेण्डरी स्कूल में कक्षा १२वीं के छात्र छात्राओं को कक्षा ९वीं से ११ वीं तक के छात्र छात्राओं द्वारा समारोह पूर्वक परम्परागत रूप से बिदाई दी गई। समारोह का शुभारंभ स्कूल संचालक और प्राचार्य निजिन बिसेन के द्वारा माँ सरस्वती एवं स्वामी विवेकानंद के छाया चित्र के समक्ष दीप प्रज्वलित कर किया गया। कु. वैशाली पथिक एवं कु. मारिनी हेड्डाक के द्वारा माँ सरस्वती की वंदना के गायन के बाद प्रमुख अतिथि का पुष्प हार एवं पुष्प गुच्छ से छात्र छात्राओं द्वारा स्वागत किया गया। तथा छात्र छात्राओं द्वारा गीतों, नृत्यों सहित सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत किये गये। इस शैक्षणिक सत्र का सर्वश्रेष्ठ छात्र का पुरस्कार छात्र निवेश नरेश कक्षा १२वीं जीव विज्ञान संकाय एवं छात्रा का पुरस्कार कु. सलोनी अमावदे कक्षा १० वीं को प्रदान किया गया। इसके अतिरिक्त अनुशासित छात्र का पुरस्कार कक्षा १२ वीं कृषि संकाय को छात्र शुभम शरणगत एवं छात्र का पुरस्कार कु. रागिनी हेड्डाक कक्षा १०वीं को प्रदान किया गया। इसके अतिरिक्त मिस फेयरवेल कु. इकरा खान कक्षा १२वीं कला संकाय एवं मिस्टर फेयरवेल अंकित कावेर कक्षा १२वीं कृषि संकाय को भोषित कर उनका सम्मान छात्र छात्राओं के द्वारा किया गया। इस समारोह में राष्ट्रीय सेवा योजना के कार्यक्रम अधिकारी अंकेश कुमार मिश्र, व्याख्याता श्रीमती अनिता मिश्रा, डी पी चैतन्य, एन के घरडे, यू के कर्ते, सुश्री ज्योति गौगम, प्राची देवारे, आंचल साहू, श्रीमती मौसमी बिसेन, भारती डोंगरे, ज्योति बिसेन, कु. मारोही डोंगरे, कुसुम नकाशे, आशा बाँकर सहित समस्त कर्मचारी उपस्थित रहे।

इबादतों की रात शब-ए-बारात आज खुदा को राजी करने रात भर चलेगा इबादतों का दौर

दुल्हन की तरह सजाया गई मस्जिदों, कब्रगाहों में भी गई आकर्षक रोशनी

पद्मेश न्यूज। बालाघाट। इबादतों की रात, शब-ए-बरात का तोफंदी तय करने वाली रात माना जाता है। यह रात इस्लामी कैलेंडर के शुजाबिक आठवें महीने शबाब की 15वीं तारीख को आती है। जो इस बार 3 फरवरी मंगलवार को आएगी इस रात में इस्लाम धर्म के मानने वाले लोग पूरे रात एक अल्लाह की इबादत करेंगे। वहीं अपने अपने गुनाहों की माफ़ी माँगेंगे। मंगलवार को आने वाली इस अजीम रात की तमाम तैयारियाँ मुस्लिम समुदाय द्वारा पूरे कर ली गई हैं। वहीं जिले भर की तमाम मस्जिदों में विभिन्न कार्यक्रमों के आयोजन को रूपरेखा तैयार कर ली गई है।

क्या है शब ए बारात

अरबी भाषा का शब्द शब ए बारात दो शब्द, शब और बारात से मिलकर बना है, जहाँ शब का अर्थ रात तो वहीं बारात का मतलब बरी होना या छूटकारा पाना होता है। अर्थात ऐसी इबादत की रात जो उनके गुनाहों से उन्हें बरी कर दे। शब ए बारात कहलाती है। इस्लामी कैलेंडर के शुजाबिक यह रात साल में एक बार उर्दू शायरान महीने की 15 तारीख को सूरज के डूबने के बाद शुरू होती है। इस्लाम में यह रात बेहद फजौलत की रात मानी जाती है। इस रात को मुस्लिम रात पर इबादत कर दुआएँ मांगते हैं और अपने गुनाहों की तोबा करते हैं। शब-ए-बारात की सारी रात इबादत और तिलावत का दौर चलता है। इस रात अपने उन परिचितों, जो दुनिया से रुखस्त हो चुके हैं, उनकी मारफित की दुआएँ की जाती हैं। इस्लामिक मान्यता के अनुसार यह रात पूर्व के समय में किए गए कर्मों का लेखा जोखा तैयार करने और आने वाले साल की तफदीर तय करने वाली मानी जाती है इसलिए इस रात की शब-ए-बारात के तौर पर जाना जाता है। ऐसा कहा जाता है कि तोबा की इस रात की अल्लाह तआला अपने बंदों का पूरे साल का हिसाब तजाला करते हैं। इसलिए इस रात को पूरी तरह इबादत में गुजारने की परंपरा है।

रखा जाएगा शाबाब का रोजा, कब्रगाहों में मारहुमों को किया जाएगा याद

इस दौरान मुस्लिम समुदाय के लोग 2 दिनों तक रोजा रख खुदा की इबादत करेंगे। शब-ए-बारात की रात दुनिया से विदा हो चुके लोगों की कब्रों पर जाकर उनके हक में मरफित की दुआ की जाएगी। मान्यताओं अनुसार इस रात को पाप और पुण्य के फेरले होते हैं, ऐसा माना जाता है की इस



दिन अल्लाह अपने बंदों के कर्मों का लेखा जोखा करता है और कई सारे लोगों को नरक या नि दोजख/जहन्नम से आजाद भी कर देता है, इसी वजह से मुस्लिम रात शब ए बारात पर रात भर जायिकर अल्लाह की इबादत करते हैं, इस दिन गरीबों में इमदद/दान करने को परंपरा है, इस दिन मुस्लिम लोग मस्जिदों में और कब्रिस्तानों में जाते हैं, इसके साथ ही घरों व मस्जिदों को सजाया जाता है और लोग पूरी रात अल्लाह की इबादत करते हुए बिताते हैं, इस दिन लोग नमाज पढ़ने के साथ अल्लाह से अपने पिछले गुनाहों की माफ़ी मांगते हैं, ऐसा माना जाता है कि इस दिन अल्लाह कई सारी रूहों को जहन्नम से आजाद करता है।

विभिन्न कार्यक्रमों के होंगे आयोजन

शब-ए-बारात के खास मौके पर कुगह-जगह मिलाद की महफिल सजेगी, कुगह की तिलावत होगी। धर्म गुरुओं का प्रवचन, दवादी सलाम के कार्यक्रम आयोजित किये जायेंगे। इसी अवसर पर मस्जिदों की मारफित के लिए कब्रिस्तान में दुआएँ पढ़ी जायेंगी। जिसके चलते कब्रिस्तान की रोशनी से जगमगाया जायेगा। शब-ए-बारात के अवसर पर मस्जिदों में भी रोशनी एवं सजावट की गई

है। शब-ए-बारात पूर्व में रोजे रखने का भी धार्मिक मान्यता के अनुसार बड़ा महत्व है।

अजीम नेमतों वाली है शबे बारात

धार्मिक मान्यता के अनुसार शबे बारात को लेकर पैगंबर हजरत मोहम्मद (सल्ल) का फरमान है कि शबे बारात का दिन आखिरत की नेमत और रहमत हसिल करने, दुनियावी आफतों, मुसीबतों दूर करने और दिली मुएद पाने का दिन है। इसलिए बंदे को चाहिये कि वह परहेजगारी के साथ अपने रव की इबादत करें। अपने दिल से जलन, हसरद को निकास दे, बंदे के अधिभार, जैसे भी हो, उसको अया कर दे, तभी अपनी इबादतों में सफल होंगे। साथ ही शबे बारात के दिन अल्लाह के महबूब बंदों को भी याद किया जाता है। जिसमें विशेष रूप से हज़रत उदैस करनी को याद माना जाति है। जिन्होंने पूरी दुनिया को अपने माँ-बाप की सेवा का उदाहरण पेश किया। साथ ही पूरी दुनिया के मुस्लिम धर्मालंबियों को नबी के रास्ते पर सच्चाई के साथ चलने का पैगाम दिया। उनके चाहते, मानने वाले शबे बारात के दिन उनके नाम से विशेष व्यंजन बनाकर गरीबों को, दोस्तों, अहवालों को बाँटकर उनको याद करते हैं और उनके वंशजों से अपने लिए दुआएँ मांगते हैं।

नाम सुधार सूचना

सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि मेरा नाम मोहम्मद शौएव शरीफ शेख (Mohammad Shood Sharif Sheikh) पिता अब्दुल शरीफ शेख (Abdul Sharif Sheikh) है। किंतु मेरे दृष्टिगत लायसंस में मेरा नाम ब्रूटिश मोहम्मद शौएव शेख (Mohammad Shood Sheikh) दर्ज हो गया है। अतः मुझे मेरे सही नाम मोहम्मद शौएव शरीफ शेख (Mohammad Shood Sharif Sheikh) पिता अब्दुल शरीफ शेख (Abdul Sharif Sheikh) के नाम से ही जाना-पहचान व पढ़ा जावे।

वास्ते सूचनार्थ

मोहम्मद शौएव शरीफ शेख
पिता अब्दुल शरीफ शेख, बालाघाट

AFFIDAVIT

I, No-5031766A, Rank- RFN/GD, Name- MUKESH KUMAR, R/O Ward No. 17 Village-Ladsada, PO-Ladsada, Tehsil-Waraseoni, District- Balaghat, State- Madhya Pradesh Pin- 481331 presently posted 30 Assam Rifles District Kiphire (Nagaland) do hereby solemnly affirm and declare that the statement made below are true and correct to the best of my knowledge, affirmation and belief :-

1. That the correct name of my spouse name is Sonam Upwanshi as per Aadhar card and PAN Card.
2. That the same of my spouse has been mentioned wrongly as Sonam in My service records.
3. That this affidavit being sworn for correction of my spouse name Sonam Upwanshi in place of mentioned wrong name Sonam in my service records.
4. That both Names Sonam Upwanshi and Sonam pertain to one and the same person.
5. That the correct date of birth of my spouse is 20/02/2002 as per Aadhar Card, PAN Card and service records.
6. That the above statements are true and correct to the best of my knowledge.

VERIFICATION

Verified at Balaghat on this 02 February 2026 that the content of my affidavit are true and correct to the best of my knowledge and belief and nothing has been concealed there from.

Date - 02/02/2026
Place- Balaghat
Witness -
Shubham Nagpure
S/o Hisaballah Nagpure
R/o - At-Bagdara Tehsil & Dist. Balaghat

Advocate
Vinita Lihare
Balaghat

In The Court Of Civil Judge Junior Division Waraseoni, District Court, Balaghat
Presiding Officer- **रश्मि बाधरी**
(आदेश 5 नियम 20 व्यवहार प्रक्रिया संहिता 1908 के अनुरूप प्रकाशन हेतु)
(RCS A/0000276/2025)
धनीराम उड्डे.....वादी
Vs
मध्यप्रदेश शासन द्वारा कलेक्टर बालाघाट.....प्रतिवादी
Process Id:- 52/2026
पेशी दिनांक:- 05/02/2026

प्रेषिती-
आगमनता पता- जिला बालाघाट मध्यप्रदेश
यह कि प्राची धनीराम उड्डे ने आपके विरुद्ध बाद वास्ते घोषणा आज्ञापक निषेधाज्ञा एवं स्थाई निषेधाज्ञा के लिए वाद स्थित किया है, आपको इस न्यायालय में सूचना के प्रकाशन के 30 दिवस के भीतर वाद का उत्तर देने के लिये उत्पसंदात / हाजिर होने के लये सम्मन किया जाता है, आप न्यायालय में स्वयं या किसी ऐसे प्लीडर (अधिवक्ता) द्वारा उत्पसंदात हो सकते हैं, जिसे सम्यक अनुरोध दिया गये हो और जो इस वाद में संबंधित सभी साक्षान कथनों का उत्तर, दे सके। आपको यह निर्देश भी दिया जाता है कि उस दिन अपनी प्रतिरक्षा का लिखित कथन प्रस्तुत करें और उस दिन ऐसे सब दस्तावेज जो आपके कब्जे या शक्ति में है पेश करें जिन पर आपका प्रतिरक्षा या मुजराई का दावा या प्रतिदान आधारित हो, और यदि आप अन्य किसी दस्तावेज पर चाहे वह आपके कब्जे या शक्ति में हो अपनी प्रत्यक्षा या मुजरा के दावे या प्रतिदावे के समर्थन में साक्ष्य के रूप में निर्भर करते हैं तो ऐसी सभी दस्तावेजों की लिखित कथन के साथ उपलब्ध की जाने वाली सूची में प्रविष्टि करें। आपको सूचित किया जाता है कि यदि आप उपर बताई गई अवधि में इस न्यायालय में उपस्थित नहीं होंगे तो वाद की एक पक्षीय सुनवाई कर उसका निपटारा आपको अनुपस्थिति में किया जायेगा। साथ ही यह भी सूचित किया जाता है कि यदि आप निराकरण पथस्थ के माध्यम से करने के इच्छुक हैं तो पीठासीन अधिकारी को अवगत करायें। यह आज तारीख 16 January 2026 को मेरे हस्ताक्षर से और न्यायालय की मुद्रा लगा कर दिया गया है।
न्यायाधीश
1. यदि किसी कारणवश उक्त तिथि को न्यायालय अवकाश पर रहेगा तो आगामी कार्यदिशर पर यह प्रकरण सुनवाई में लिया जायेगा।

बारबेड वायर (काटेदार तार) एवं चेन लिंक जाली
उचित दाम पर उपलब्ध
लघु उद्योग निगम ओपाल से संबद्ध
निर्माता
तिरुपति इंजीनियरिंग वर्क्स
मयूर टॉकिंग के सामने हनुमान चौक, बालाघाट
फ़ोन:- 07632-243531
जी:- 8989976858, 9425139998

आवश्यकता है दो छोटे बच्चों की देखरेख करने और घरेलू कार्य करने के लिये युवती की आवश्यकता है
आकर्षक वेतनमान
6269524236
9009712121

दाव दुकान में कार्य हेतु लड़कों की आवश्यकता है
योग्यता- 10वीं पास
पार्ट टाइम जॉब
वाले संपर्क न करें।
वेतन-योग्यतानुसार
कार्य सीखे व्यक्ति को प्राथमिकता
संपर्क-9340308019

सांझ नारबोदे
आपकी जन्मदिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं
रामू - कोशल नारबोदे पापा-मन्नी अर्जुन - नीतू नारबोदे चाचा-चाची हार्दिक नारबोदे - गाई गणेश - टीना बाबने मामा-मामी एवं समस्त नारबोदे परिवार आनंदोदा दिया लालबर्वा

न्यूज़ गैलरी

कीटनाशक का छिड़काव बना काला, खेत से लौटते ही टूटा किसान दिलीप का दम

पद्मेश न्यूज़। बालाघाट। खेत में कितना से दवाई का छिड़काव करते समय कीटनाशक दवाई के प्रभाव में आने से बेहोश एक कृषक की जिला अस्पताल में उपचार के दौरान मौत हो गई। मुकदमा कृषक दिलीप पिता चेतनम ठाकुर 53 वर्ष ग्राम कोकना थाना किनापुर निवासी है। जिला अस्पताल पुलिस ने इस कृषक का शव पोस्टमार्टम करवा कर उसके परिजनों को सौंप दिया है।

ग्राम जानकारी के अनुसार दिलीप ठाकुर अपने परिवार के साथ खेती किसानों करता था जिसके परिवार में पत्नी, कारण बाई ठाकुर के अलावा दो लड़के और एक लड़की है। तीनों की शादी नहीं हो पाई है। बताया गया है कि 2 फरवरी को सुबह दिलीप ठाकुर अपने खेत वहाँ की फसल में कीटनाशक दवाई का छिड़काव करने के लिए गया था। कीटनाशक दवाई का छिड़काव करने के बाद 10:30 बजे दिलीप ठाकुर अपने घर आया और अपनी पत्नी को बताए कि उसे चक्कर आ रहा है। पत्नी ने उसे बोली की मुँह में कपड़ा बांधकर कीटनाशक का दवाई का छिड़काव करना था किंतु दिलीप ने उसे बोला कि मैं मुँह में कपड़ा नहीं बांधूँ था। जिसके बाद वह उल्टी करने लगा था। हालात खराब होने पर दिलीप ठाकुर को उसके परिजनों ने किरानपुर के अस्पताल में भर्ती किए थे। जहाँ 2 घंटा इलाज के बाद भी दिलीप ठाकुर के स्वास्थ्य में सुधार नहीं होने पर उसे जिला अस्पताल बालाघाट रेफर किया गया था। जिला अस्पताल में भर्ती करने के बाद 1 घंटे चल उपचार के दौरान कृषक दिलीप ठाकुर की मौत हो गई। जिला अस्पताल पुलिस ने शव पंचनामा कार्यवाही पश्चात कृषक दिलीप ठाकुर का शव पोस्टमार्टम करवा कर उसके परिजनों को सौंप दिया है और थारा 194 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता के तहत वर्ग कायम कर मर्ग डायरी अंतिम कार्यवाही हेतु घटना स्थल से संबंधित पुलिस थाना किनापुर भिजवा दी है।

इस दर्दनाक घटना ने एक बार फिर यह सवाल खड़ा कर दिया है कि कीटनाशक दवाइयों के छिड़काव के दौरान सुरक्षा उपायों के प्रति लापरवाही कितनी जानबूझ साबित हो सकती है। खेत में मेहनत कर परिवार का पेट पालने वाला किसान खुद ही असुरक्षित हो जाए, तो परिणाम कितना भयावह हो सकता है—यह घटना उसी की दुबड़ा मिसाल है।

हिन्दू संगठनों ने किया घोटी नन्दोरा के 10 मुस्लिम परिवारों का कथित सामाजिक बहिष्कार!!

पूर्व विधायक किशोर समरीते ने की घोटी-नंदोरा में पुलिस फ्लैग मार्च और न्यायिक जांच की मांग

पद्मेश न्यूज़। बालाघाट।

संयुक्त क्रांति पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं पूर्व विधायक किशोर समरीते ने बालाघाट जिले की लॉजी लहमील के ग्राम घोटी और नंदोरा में 10 मुस्लिम परिवारों के कथित सामाजिक बहिष्कार के मामले को गंभीर बनाते हुए केंद्रीय



गृह मंत्रालय से जांच कराने और दोनों गांवों में पुलिस फ्लैग मार्च कराने की मांग की है। श्री समरीते ने अपने जारी बयान में कहा कि ग्राम घोटी और नंदोरा विगत दो वर्षों से गौहत्या और गोमय से जुड़े मामलों को लेकर चर्चा में रहे हैं, लेकिन वर्तमान में यहाँ 10 मुस्लिम परिवारों के सामाजिक बहिष्कार का मामला सामने आना अत्यंत चिंताजनक है।

उन्होंने आरोप लगाया कि इतनी गंभीर घटना के बावजूद थाना लॉजी, पुलिस मुख्यालय और राज्य स्तर के



अधिकारी मामले को दबाने का प्रयास कर रहे हैं। जबकि खुफिया एजेंसियाँ भी इस पर मौन साधे हुए हैं। पूर्व विधायक ने कहा कि गांवों में कथित रूप से मुस्लिम समुदाय के लोगों को किराने का सामान देने से मना किया जा रहा है। नाई द्राव दाही या बाल कटवाने से इनकार किया जा रहा है और कीटनाशक के माध्यम से गांव में मुनादी और सामाजिक बहिष्कार को घोषणा कराई गई है। उन्होंने आरोप लगाया कि गांव के सरपंच, सचिव, जनप्र सदन और जिला पंचायत सदस्य भी इस बहिष्कार के समर्थन में खड़े नजर आ रहे हैं।

श्री समरीते ने यह भी आरोप लगाया कि गांव के मंदिरों और चौराहों पर धार्मिक झंडे लगाकर भड़काऊ भाषण (हेट स्पीच) दिए जा रहे हैं, जिससे गांव का सामाजिक माहौल तनावपूर्ण होता जा रहा है। उन्होंने कहा कि बहिष्कार परिवारों के छोटे बच्चे स्कूल जाने से डर रहे हैं और महिलाएँ सच के वातावरण में जीवन जीने को मजबूर हैं। पूर्व विधायक ने पूरे मामले को की न्यायिक जांच कराने, बहिष्कार परिवारों की संविधान द्वाारा प्रदात नागरिक अधिकार तत्काल बहाल कराने तथा दंगा भड़काने वाले अशामाजिक तत्वों के खिलाफ कठोर कार्रवाई की मांग की है। उन्होंने चेतावनी दी कि यदि प्रशासन ने समय रहते निष्पक्ष और सख्त कदम नहीं उठाए, तो यह मामला कानून-व्यवस्था और सामाजिक सौहार्द के लिए गंभीर खतरा बन सकता है।

निष्पक्ष नहीं हुए जिला अधिवक्ता संघ के चुनाव 50 मत अधिक गणना का आरोप

चुनाव अधिकारी ने आरोपों को बताया बेबुनियाद, कहा- पारदर्शिता से सम्पन्न कराए गए हैं चुनाव

पद्मेश न्यूज़। बालाघाट। पिछले माह 17 जनवरी को संपन्न हुए जिला अधिवक्ता संघ चुनाव में गड़बड़ी किए जाने के आरोप लगा रहे हैं। यह आरोप किसी और ने नहीं, बल्कि जिला अधिवक्ता संघ के पूर्व अध्यक्ष एवं वर्तमान चुनाव में अध्यक्ष पद के लिए खड़े प्रत्याशी आनंद टेंभरे ने लगाया है। जिन्होंने इस चुनाव में मतदान प्रक्रिया, मतगणना 50 मत अधिक गणना करने सहित अन्य बिंदुओं की जांच कर उन्हें ईसाफ दिलाए जाने की गुहार लगाई है। जिसमें उन्होंने स्पष्ट कर दिया कि यदि मामले की जांच नहीं हुई और उन्हें ईसाफ नहीं मिला तो वह ईसाफ को लेकर हाई कोर्ट जाएंगे। एक तरफ पूर्व अध्यक्ष एवं वर्ष 2026 में 17 जनवरी को संपन्न हुए इस चुनाव में अध्यक्ष पद के लिए खड़े प्रत्याशी आनंद टेंभरे ने यह आरोप लगाया लगाया हुए अपने साक्षियों के साथ सोमवार को एसपी कार्यालय में एक जापन सीप है जिसमें उन्होंने मामले में ईसाफ दिए जाने की गुहार लगाई है। तो दूसरी तरफ चुनाव अधिकारी ने 17 जनवरी को सम्पन्न हुई चुनाव



प्रक्रिया को पूर्ण पारदर्शी बनाते हुए पूर्व अध्यक्ष द्वारा लगाए गए सभी आरोपों की झूठ व बे-बुनियाद स्मरण है।

तो हाईकोर्ट में दायर करेंगे याचिका-आनंद टेंभरे

जिला अधिवक्ता संघ चुनाव में अध्यक्ष

पद के प्रत्याशी रहे पूर्व अध्यक्ष आनंद टेंभरे ने बताया कि जिला अधिवक्ता संघ के चुनाव में हुई गड़बड़ी की शिकायत, आज हमने एसपी से करते हुए जांच और कार्यवाही की मांग की है। उन्होंने बताया कि मतदान के बाद जो मतदाता की सख्ता बताई गई थी। उससे

50 मत ज्यादा मत, मतगणना में निकले। यही नहीं बल्कि, मतदान के दौरान, मतदाता अधिवक्ताओं ने जो दस्तावेज दिए थे। उस दस्तावेज की सर्टिफाइड कॉपी भी नहीं दी जा रही है। बल्कि चुनाव अधिकारी बताते हैं कि वह किसी ने ले जा लिया है या फिर चोरी हो गई है। जिसमें अब तक उन्होंने इस पर कोई कार्यवाही नहीं की। जिससे यह साफ होता है कि जिला अधिवक्ता संघ के चुनाव में गड़बड़ी की गई है जिसकी जांच की मांग हमने दिए आदेश में की है। उन्होंने बताया कि यदि जांच नहीं होगी तो वह हाईकोर्ट में याचिका दायर करेंगे।

सभी आरोप निराधार हैं- हीरीश

हालांकि प्रत्याशियों के लगाए गए आरोपों को लेकर जिला निर्वाचन अधिकारी अधिवक्ता हीरीश नागपुर ने बताया कि सभी आरोप निराधार हैं। हमने चुनाव को लेकर सख्त अधिका संघ के निर्दिष्टानुसार चुनाव पूरी पारदर्शिता पं तकिक से कराए हैं। आरोपकर्ता, हारने के बाद यह आरोप लगा रहे हैं।

डॉ. घनश्याम परते ने उप संचालक पशु चिकित्सा विभाग का पदभार संभाला

पद्मेश न्यूज़। बालाघाट। वरिष्ठ पशु चिकित्सक डॉ. घनश्याम परते ने पशु चिकित्सा विभाग में उप

प्रयास किए जाएंगे। आबारा श्रानों की बढ़ती समस्या को लेकर पशु गण सवाल पर डॉ. परते ने बताया कि



पूर्व में जिला पशु चिकित्सालय के माध्यम से निष्कूल वैक्सिनेशन शिफर आयोजित कर आबारा श्रानों का टीकाकरण और बर्धियाकरण किया गया है। उन्होंने स्पष्ट किया कि आबारा पशुओं और श्रानों के प्रबंधन की मुख्य जिम्मेदारी नगरपालिका प्रशासन की होती है, लेकिन इस कार्य में यदि तकनीकी सहयोग की आवश्यकता पड़ेगी तो पशु चिकित्सा विभाग पूरी तरह सहयोग करने के लिए तैयार है। उन्होंने कहा कि विभाग और नगरपालिका के समन्वय से ऐसे दोस अधिक से अधिक लाभ मिल सकें। उन्होंने बताया कि जिला दुध उत्पादन के क्षेत्र में पहले से ही अच्छे प्रदर्शन कर रहा है और प्रयास रहेगा कि पशुपालकों की दूध का बेहतर मूल्य प्राप्त हो सके। इसके साथ ही यह भी सुनिश्चित किया जाएगा कि सरकारी योजनाओं की कार्यान्वयन और लाभ अंतिम व्यक्ति तक पहुंचे। उन्होंने कहा कि किसानों और पशुपालकों से जुड़ी समस्याओं के निराकरण के लिए विभाग लगातार सक्रिय रहेगा और समयवद्ध समाधान के

प्रयास किए जाएंगे। आबारा श्रानों की बढ़ती समस्या को लेकर पशु गण सवाल पर डॉ. परते ने बताया कि पूर्व में जिला पशु चिकित्सालय के माध्यम से निष्कूल वैक्सिनेशन शिफर आयोजित कर आबारा श्रानों का टीकाकरण और बर्धियाकरण किया गया है। उन्होंने स्पष्ट किया कि आबारा पशुओं और श्रानों के प्रबंधन की मुख्य जिम्मेदारी नगरपालिका प्रशासन की होती है, लेकिन इस कार्य में यदि तकनीकी सहयोग की आवश्यकता पड़ेगी तो पशु चिकित्सा विभाग पूरी तरह सहयोग करने के लिए तैयार है। उन्होंने कहा कि विभाग और नगरपालिका के समन्वय से ऐसे दोस अधिक से अधिक लाभ मिल सकें। उन्होंने बताया कि जिला दुध उत्पादन के क्षेत्र में पहले से ही अच्छे प्रदर्शन कर रहा है और प्रयास रहेगा कि पशुपालकों की दूध का बेहतर मूल्य प्राप्त हो सके। इसके साथ ही यह भी सुनिश्चित किया जाएगा कि सरकारी योजनाओं की कार्यान्वयन और लाभ अंतिम व्यक्ति तक पहुंचे। उन्होंने कहा कि किसानों और पशुपालकों से जुड़ी समस्याओं के निराकरण के लिए विभाग लगातार सक्रिय रहेगा और समयवद्ध समाधान के

जिला संचालित की संचार एवं संकर्म समिति की बैठक स्थगित

पद्मेश न्यूज़। बालाघाट। जिला पंचायत की संचार एवं संकर्म समिति की बैठक 05 फरवरी को दोपहर 2:00 बजे जिला पंचायत कार्यालय बालाघाट के सभागार में आयोजित की गई थी। उक्त बैठक अभिरक्षार्थ कार्यों से स्थगित कर दी गई है। आगामी बैठक को सूचना पृथक से दी जाएगी।

यूजीसी कानून के विरोध में सकल सामान्य समाज का आक्रोश, रैली निकालकर साँपा ज्ञापन

पद्मेश न्यूज़। बालाघाट। यूजीसी कानून के विरोध में सकल सामान्य समाज के बैनर तले गहर में विरोध प्रदर्शन किया गया। इस दौरान समाज के सदस्यों ने एक विशाल रैली निकाली, जो न्यायिक राम मंदिर से प्रारंभ होकर गहर के प्रमुख मार्गों से होते हुए कालीपुतली चौक तक पहुंची। रैली में बड़ी संख्या में लोग शामिल हुए और हाथों में रजिस्टार व बैनर



लेकर कानून के खिलाफ नारेबाजी की। कालीपुतली चौक पर सकल सामान्य समाज के पदाधिकारियों ने समा को संबोधित करते हुए यूजीसी कानून को जनहित के खिलाफ बताया और इसे तत्काल वापस लेने की मांग की। वक्ताओं ने कहा कि यह कानून शिक्षा व्यवस्था, जजों और आम नागरिकों के हितों को धमका रहा है, जबकि किसी भी व्यक्ति में स्वीकार नहीं किया जा सकता। प्रदर्शन के पश्चात सामान्य समाज के प्रतिनिधि कलेक्टर कार्यालय पहुंचे, जहाँ उन्होंने महामंत्री राहुल सिंह के नाम एक जापन कलेक्टर को सौंपा। जापन के माध्यम से केंद्र सरकार से यूजीसी कानून को निरस्त करने की मांग की गई। बोते दिनों केंद्र सरकार द्वारा जाए गए यूजीसी कानून को लेकर देशभर के साथ-साथ जिले में भी विरोध के स्वर उठने लगे हैं। इसी क्रम में सकल सामान्य समाज द्वारा इस कानून के खिलाफ आंदोलन को रूपरेखा तैयार की गई। पहले

1 फरवरी को सकल सामान्य समाज एवं व्यापारियों की बैठक आयोजित कर विरोध प्रदर्शन की रणनीति बनाई गई, जिसके बाद 2 फरवरी को शहर में व्यापक विरोध प्रदर्शन किया गया। इस संबंध में सकल सामान्य समाज के पदाधिकारी अजित शर्मा ने बताया कि संगठन द्वारा जाए गए एक यूजीसी कानून का विरोध किया जा रहा है। उनका कहना है कि यह कानून शिक्षा और शिक्षा व्यवस्था में भी नहीं है, इसलिए सकल सामान्य समाज सरकार से इसे तत्काल वापस लेने की मांग कर रहा है। इसी मांग को लेकर यह प्रदर्शन आयोजित किया गया। अजित शर्मा ने यह भी आपन अनुमति मिलने के बावजूद जिला प्रशासन वहां जापन देने नहीं पहुंचे। इससे

प्रदर्शनकारियों में नाराजगी देखी गई। प्रशासन के खरबे से आक्रोशित सकल सामान्य समाज के सदस्यों ने काली पुतली चौक से आक्रोश रैली निकाली, जो शहर के प्रमुख मार्गों से होते हुए कलेक्टर कार्यालय के मुख्य द्वार तक पहुंची। वहां भी कड़ी समर्थन तक जापन सीपों को लेकर विरोध प्रदर्शन किया गया। बाद में सकल सामान्य समाज के प्रतिनिधियों ने महामंत्री राहुल सिंह के नाम एक जापन डिप्टी कलेक्टर को सौंपा। जापन के माध्यम से यूजीसी कानून को वापस लेने की मांग दोहराई गई।

संयुक्त विभाग पेंशनर संघ की मासिक बैठक सम्पन्न विभिन्न बिंदुओं पर की गई चर्चा, नए सदस्यों को संघ में किया शामिल

पद्मेश न्यूज़। बालाघाट। वर्षों से लंबी अपनी विभिन्न मांगों को लेकर संयुक्त विभाग

जाने, बकाया महंगाई राहत का एकमुश्त परियर्स देने, म.प्र./छत्तीसगढ़ की धारा 49(6)

निर्भा और कई महत्वपूर्ण सुझाव दिए, जिन्हें संघ की कार्ययोजना में शामिल किया जाएगा।

संयुक्त विभाग पेंशनर संघ के बैठक के दौरान संघ के वरिष्ठ सदस्यों ने पेंशन, वेतन संशोधन, स्वास्थ्य सुविधाएं और सामाजिक सुरक्षा जैसे महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा की। वही नूतन पेंशनरों ने सदस्यों की पेशानियों को सुनकर त्वरित समाधान के लिए रणनीति तय की गई जिसपर सभी से सहयोग की अपील की गई।

इन बिंदुओं पर हुई चर्चा

संयुक्त विभाग पेंशनर संघ के बैनर तले आयोजित इस बैठक में खास तौर पर मुख्यालय में आयोजित होने वाली बैठकों के लिए एक सर्व सुविधा युक्त भवन देने, केंद्र सरकार के समान 7 प्रतिशत मंहगाई राहत दिए

अविलम्ब विलोपित करने, आयुधमान स्वास्थ्य बीमा का लाभ सभी पेंशनरों को देने, समस्त सेवानिवृत्त शिक्षकों के लॉचर अर्जित अवकाश का प्रकरण का पूर्ण निराकरण करने, सेवा निवृत्त पेंशनरों एक वेतन वृद्धि का लाभ देने से सहित अन्य मांगों को लेकर सख्त विस्तार चर्चा की गई।

प्रशासनिक अधिकारियों से चर्चा

रक निकाला जाएगा समाधान संघ ने निर्णय लिया कि आगामी महीनों में विशेष बैठकें आयोजित की जाएंगी, ताकि पेंशनरों की समस्याओं और सामूहिक समस्याओं का प्रभावी समाधान किया जा सके। बैठक में उपस्थित सदस्यों ने सक्रिय भागीदारी

संघ के पदाधिकारियों ने आश्वासन दिया कि पेंशनरों के हितों की रक्षा के लिए निरामित संवाद और समन्वय जारी रहेगा। आवश्यकता पड़ने पर प्रशासनिक अधिकारियों से विचलित मुद्दों पर भी बातचीत की जाएगी।

सबसे ज्यादा वन विभाग के कर्मचारियों की समस्याएं हैं- बीएल चौधरी

संयुक्त विभाग पेंशनर संघ अध्यक्ष बीएल चौधरी और वरिष्ठ पदाधिकारी श्री मानवेंद्रकर ने संयुक्त रूप से बताया कि आज संघ की मासिक बैठक का आयोजन किया गया था, इसमें सबसे अधिक समस्याएं वन विभाग के कर्मचारियों की सामने आई हैं। कुछ कर्मचारों

किया गया था लेकिन बावजूद भी उन्हें विभाग निर्मित कर्मचारी नहीं माना रहा है। कुछ के अतिरिक्त अवकाश के मामले लॉचर हैं। इस पर कर्मचारी हार्दिकता भी गए थे, जहां से उन्हें न्याय भी मिला था, लेकिन विभागिय अधिकारियों ने न्यायालय के आदेश के अनुसार कार्यवाही नहीं की, कोर्ट आबकूद इसके भी समस्या का समाधान नहीं हो पाया है। हम संघ के माध्यम से डीएफए से मुलाकात कर इस प्रकरण का समाधान निकालने के कोशिश करेंगे। इसके अलावा अन्य समस्याओं भी हैं, जिसके समाधान को लेकर चर्चा की गई। इस दौरान जिला महामंत्री नारायण शर्मा, जिला संरक्षक आर. एस. वैस, डी.सी. डहरवाल, एस. जे. कुर्से, जिला उपअध्यक्ष श्रीमती ज्योत्सना स्वामी, आर. के. नन्दनवार, एस. डी. ए. देवराज विसेन, संचालक वन विभाग सोमलोक, जिला प्रवक्ता सतीशचन्द्र दुबे, संयुक्त सचिव एस.डी. पटेल, सचिव वन विभाग सूरजलाल कावडे, सहसचिव एस.आर. शिवसेन, पी.डी. रावणदी, आर.एस. बबले, इशमलाल पंचेकर आर.एस. आर. पंचेकर सहित अन्य पदाधिकारी सदस्य प्रमुख रूप से उपस्थित रहे।

किया गया था लेकिन बावजूद भी उन्हें विभाग निर्मित कर्मचारी नहीं माना रहा है। कुछ के अतिरिक्त अवकाश के मामले लॉचर हैं। इस पर कर्मचारी हार्दिकता भी गए थे, जहां से उन्हें न्याय भी मिला था, लेकिन विभागिय अधिकारियों ने न्यायालय के आदेश के अनुसार कार्यवाही नहीं की, कोर्ट आबकूद इसके भी समस्या का समाधान नहीं हो पाया है। हम संघ के माध्यम से डीएफए से मुलाकात कर इस प्रकरण का समाधान निकालने के कोशिश करेंगे। इसके अलावा अन्य समस्याओं भी हैं, जिसके समाधान को लेकर चर्चा की गई। इस दौरान जिला महामंत्री नारायण शर्मा, जिला संरक्षक आर. एस. वैस, डी.सी. डहरवाल, एस. जे. कुर्से, जिला उपअध्यक्ष श्रीमती ज्योत्सना स्वामी, आर. के. नन्दनवार, एस. डी. ए. देवराज विसेन, संचालक वन विभाग सोमलोक, जिला प्रवक्ता सतीशचन्द्र दुबे, संयुक्त सचिव एस.डी. पटेल, सचिव वन विभाग सूरजलाल कावडे, सहसचिव एस.आर. शिवसेन, पी.डी. रावणदी, आर.एस. बबले, इशमलाल पंचेकर आर.एस. आर. पंचेकर सहित अन्य पदाधिकारी सदस्य प्रमुख रूप से उपस्थित रहे।

गेंद पर ८० रन एवं एक विकेट लेने पर दिया गया। द्वितीय मैच में मैंन ऑफ द मैच मोहित राउत को १७ रन एवं दो विकेट लेने पर दिया गया।

मतदाता सूची के गहन पुनरीक्षण को लेकर रोल प्रेक्षक मनीष सिंह ने राजनैतिक दलों की ली बैठक

पद्मेश न्यूज । बालाघाट ।

भारत निर्वाचन आयोग द्वारा निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार बालाघाट जिले में भी मतदाता सूची के गहन पुनरीक्षण (एसआईआर-2026) का कार्य किया जा रहा है। आयोग द्वारा बालाघाट जिले के लिए नियुक्त रोल प्रेक्षक सचिव परिवहन विभाग एवं मध्यप्रदेश सुपाम परिवहन सेवा निगम के प्रबंध निदेशक मनीष सिंह ने 02 फरवरी को कलेक्टर सभाकक्ष में राजनैतिक दलों के प्रतिनिधियों के साथ बैठक कर मतदाता सूची के गहन पुनरीक्षण पर चर्चा की। बैठक में कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी गुणाल मीना, उप जिला निर्वाचन अधिकारी श्री जीपीएस धुर्वे एवं राजनैतिक दलों के प्रतिनिधि उपस्थित थे।

रोल प्रेक्षक मनीष सिंह ने बैठक में कहा कि बालाघाट जिले की मतदाता सूची का लिंगानुपात 1010 एवं ईपिक रसियो 68.37 प्रतिशत है जो कि बहुत अच्छा है। उन्होंने कहा कि मतदाता सूची के गहन पुनरीक्षण के दौरान 18 से 19 आयु वर्ग के सभी युवाओं के नाम मतदाता सूची में शामिल करे। एसआईआर के दौरान जिन मतदाताओं की मैपिंग नहीं हो पायी है एवं जिनके ईन्यूमरेशन फार्म जमा नहीं हो पाए हैं, उनकी सुनवाई के दौरान दस्तावेजों का परीक्षण कर पात्र होने पर उनके नाम



सूची में शामिल किये जाए। रोल प्रेक्षक श्री सिंह ने राजनैतिक दलों के प्रतिनिधियों से कहा कि वे प्रत्येक मतदान केंद्र पर अपने बीएलए अवस्था नियुक्त करें। बैठक में बताया गया कि बालाघाट जिले में कुल मतदाताओं की संख्या 13 लाख 21 हजार 494 है। इसमें पुरुष मतदाता 06 लाख 57 हजार 340, महिला मतदाता 06 लाख 64 हजार 146 एवं थर्ड जेंडर 08 मतदाता शामिल हैं। जिले में सर्विस वोटर की संख्या 1515 है और 18 से 19 आयु वर्ग के युवा मतदाताओं की संख्या 19001 है। मतदाता सूची के पुनरीक्षण के दौरान नाम

शामिल करने के लिए 15 हजार 21 फार्म-6, नाम हटाने के लिए 2896 फार्म-7 एवं नाम संशोधन के लिए 7299 फार्म-8 प्राप्त हुए हैं। इनमें से 12 हजार 517 फार्म-6 का, 2258 फार्म-7 एवं 5365 फार्म-8 का निराकरण कर दिया गया है। जिले में कुल 1785 मतदान केंद्र हैं इनमें से 1675 मतदान केंद्रों पर भारतीय जनता पार्टी एवं भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा बीएलए नियुक्त किये गए हैं। जबकि बहुजन समाज पार्टी द्वारा 813 मतदान केंद्रों पर बीएलए नियुक्त किये गए हैं। बैठक में बताया गया कि मतदाता सूची के गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) के दौरान

95.45 प्रतिशत मतदाताओं के ईन्यूमरेशन फार्म का डिजिटलाइजेशन किया गया है। 6824 मतदाता नो मैपिंग वाले पाए गए हैं और 62 हजार 406 मतदाताओं के ईन्यूमरेशन फार्म जमा नहीं हो पाए हैं। इनमें से 18 हजार 211 को मृत्यु, 7779 को अनुपस्थिति, 32 हजार 433 के अन्य स्थान पर स्थायी रूप से शिफ्ट होने, 3843 के नाम अन्य स्थान पर दर्ज होने एवं 140 के अन्य कारणों से ईन्यूमरेशन फार्म जमा नहीं हो पाये हैं।

खेलो एमपी यूथ गेम्स में रवि प्रकाश बिसेन ने स्वर्णिम परचम फहराया

पद्मेश न्यूज । बालाघाट । खेलो एमपी यूथ गेम्स 2025-26 में बालाघाट जिले के युवा एथलीटों ने राजस्थान प्रदेश के खिलाफ रविवार को ओलंपिक के रूप में पहचान बना चुके इस प्रतिस्पर्धी



आयोजन में बालाघाट जिले के विकासखंड किरानापुर अंतर्गत ग्राम माराठ बट्टी निवासी प्रतिभागीतांशु खिलौड़ी रवि प्रकाश बिसेन ने इथलेटिक्स की 110 मीटर हर्डल्स, 400 मीटर हर्डल्स एवं 4m100 मीटर रिले रैस में तीन स्वर्ण पदक जीतकर गोल्डन बॉय का खिताब अपने नाम किया। 4m100 मीटर रिले रैस में रवि प्रकाश के साथ रविंद बिशनगर, देवेंद्र पाण्डी एवं खिखल अरवे ने संयुक्त रूप से शानदार प्रदर्शन करते हुए स्वर्ण पदक दिवाया। खेलो एमपी यूथ गेम्स 2025-26 का आयोजन

10 जनवरी से 31 जनवरी तक प्रदेश के 55 जिलों, 8 संभागों एवं 9 शहरों में 27 खेल विभागों में किया गया, जिसका स्लोान मध्य प्रदेश की जय - हम सब की विजय रहा। एथलेटिक्स मेडल टैली में बालाघाट जिले ने प्रदेश में दूसरा स्थान अर्जित किया, वहीं भाला फर्क में प्रकाश मरावी ने रजत एवं गुरुर दशरही ने कांस्य पदक जीतकर जिले का मान बढ़ाया। तीन स्वर्ण पदक जीतने वाले रवि प्रकाश बिसेन को बेस्ट एथलीट रनर-अप ट्राफी से मध्य प्रदेश के राज्यपाल मंगुभाई छानभाई पटेल, खेल मंत्री विश्वास सागर एवं खेल एवं युवा कल्याण विभाग के संचालक श्री राकेश गुप्ता द्वारा सम्मानित किया गया। वर्तमान में रवि प्रकाश मध्य प्रदेश एथलेटिक्स अकादमी भोपाल के टी.टी. नगर स्टेडियम में सीआईएएफ के सीनियर खिलाड़ी हैं।

हिरोश चौधरी के मार्गदर्शन में प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे हैं तथा उनका लक्ष्य अंतरराष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में देश के लिए पदक जीतना है। इस उपलब्धि पर जिला एथलेटिक्स संघ, खेल विभाग, प्रशिक्षकों एवं खेल प्रेमियों द्वारा सभी खिलाड़ियों को शुभकामनाएं एवं हार्दिक शुभकामनाएं दी गई हैं। बिसेन सह सिद्ध होता है कि सभी सांस्कृतिक और क्रीड़ा क्षेत्र से सामान्य अर्थवत्तों के खिलाड़ी भी राष्ट्रीय स्तर पर अपनी पहचान बना सकते हैं।

धान खरीदी का परिवहन, हेल्लपाईन के लंबित मामलों और प्रसूति सहायता सहित अन्य प्रकरणों के निराकरण के निर्देश टीएल बैठक में कलेक्टर ने की समय सीमा प्रकरणों की हुई समीक्षा

पद्मेश न्यूज । बालाघाट । 02 फरवरी को कलेक्टर सभाकक्ष में टीएल बैठक का आयोजन किया गया। इस बैठक में कलेक्टर मंगल मीना ने विभिन्न विभागों के समय सीमा संबंधी प्रकरणों की वितरित से समीक्षा की और अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। बैठक में जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी श्री अभिषेक सराफ, अपर कलेक्टर जीएस धुर्वे, श्री डीपी बर्मन, संयुक्त कलेक्टर राहुल नायक, डिप्टी कलेक्टर दीपक कौर एवं अन्य विभागों के अधिकारी उपस्थित थे। बैठक में सभी एसओएस, तहसीलदार, जपद सीईओ एवं नगरीय निकायों के मुख्य नगर प्रशासन अधिकारी वॉर्डियों कॉन्फ्रेंस के माध्यम से उपस्थित थे।

बैठक में कलेक्टर श्री मीना ने जिला आपूर्ति अधिकारी को निर्देशित किया कि समर्थन शीघ्र पर कर को गई धान का केंद्रों से परिवहन कर शीघ्र गोदामों में पहुंचाया जाए। जिले में धान के भंडारण के लिए नये अधिग्रहित गोदामों में धान का परिवहन कर पहुंचाने के निर्देश दिये गए। इस दौरान बताया गया कि 26 हजार 293 मीट्रिक टन धान का



परिवहन किया जाना शेष है और यह कार्य एक सप्ताह में पूर्ण कर लिया जाए।

बैठक में कलेक्टर श्री मीना ने सीएम हेल्लपाईन के लंबित प्रकरणों का शीघ्र निराकरण करने के सभी अधिकारियों को निर्देश दिये। सहायक आयुक्त जनजातीय कार्य विभाग को बस्ती विकास के प्रस्ताव तैयार कर स्वीकृति के लिए शासन को भेजे। इसके साथ ही उन्हें आहार अनुदान संबंधी आवेदनों का शीघ्रता से निराकरण करने के निर्देश दिये गए। सभी अधिकारियों को संकल्प से समाधान

अभियान के अंतर्गत लगाये जा रहे शिविरों में प्राप्त आवेदनों को मीके पर ही निराकरण करने के निर्देश दिये गए। राजस्व अधिकारियों को बी-1 वाचन एवं फीटी दर्ज करने व सीमांकन के लंबित प्रकरणों का शीघ्र निराकरण करने कहा गया। बैठक में मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी तथा सचिव सर्जन को निर्देशित किया गया कि प्रसूति सहायता के प्रकरणों का शीघ्रता से निराकरण किया जाए और पात्र महिलाओं का राशि का वितरण किया

जाए। सहायक संचालक मृत्योद्योग को निर्देशित किया गया कि मंगरवा एवं अन्य योजनाओं के अंतर्गत बने सभी तालाबों में मत्स्य पालन किया जाना सुनिश्चित करें। स्व-रोजगार योजनाओं वाले विभागों के अधिकारियों को निर्देशित किया गया कि स्वरोजगार योजनाओं वाले छात्र प्रकरण में शीघ्रता से छात्र वितरण करएं।

हिंदी भाषा के प्रचार-प्रसार एवं क्रियान्वयन की हुई विस्तृत समीक्षा नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति की द्वितीय छ:माही अर्धवार्षिक समीक्षा बैठक संपन्न

पद्मेश न्यूज । बालाघाट । हिंदी भाषा के प्रभावी क्रियान्वयन और उसके प्रचाडप्रसार को बढ़ावा देने के उद्देश्य से नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति (नगरभाषा), बालाघाट द्वारा द्वितीय छ:माही अर्धवार्षिक समीक्षा बैठक का आयोजन आकाशवाणी केंद्र बालाघाट में किया गया। यह बैठक गृह मंत्रालय, भारत सरकार के निर्देशानुसार आयोजित की गई।

बैठक का शुभारंभ मुख्य अतिथि श्री हजारीलाल, कमांडेंट 123वीं बटालियन भारतीय, विशेष अतिथि श्री कैप्टन गिल, कमांडेंट 207 बटालियन किरानापुर, खान प्रवेशक मंगल बालाघाट श्री विवेक कुमार, नगरास के अध्यक्ष एवं वैज्ञानिकद्वय, केंद्रीय रेशम बोर्ड बालाघाट के सदस्य सचिव

डा. बाबकर दत्ता मदन के मुख्य अतिथ्य में दीप प्रज्वलन कर किया गया। कार्यक्रम में सहायक निदेशक श्री कुंवर विक्रम सिंह, जिला अग्रणी बैंक प्रबंधक श्री सुनील कुमार, प्रसारक अधिकारी श्री धीरज कुमार सहित नगरास के सदस्य कार्यवाहों के अधिकारी उपस्थित रहे। अर्धवार्षिक समीक्षा बैठक के दौरान सर्वप्रथम बालाघाट में स्थित केंद्र सरकार के विभिन्न मंत्रालयों, बैंकों, अधिशासी संस्थानों एवं उपक्रमों के प्रतिनिधियों का परिचय कराया गया। इसके बाद नगरास अध्यक्ष डा. बाबकर दत्ता द्वारा सदस्य कार्यवाहों की राजभाषा प्राप्ति रिपोर्ट का अवलोकन एवं समीक्षा की गई। उन्होंने रिपोर्ट में पाई गई सुझावों का समाधान करते हुए सभी कार्यवाहों से राजभाषा संबंधी कार्यों पर विशेष ध्यान देने का आग्रह किया। बैठक में राजभाषा अधिनियम की धारा 3(3) के अंतर्गत जारी



पत्राचार, हिंदी में कामकाज की प्रगति तथा कार्यवाहों में हिंदी के अधिकाधिक प्रयोग पर भी विचार से चर्चा की गई। मुख्य अतिथि कमांडेंट हजारीलाल ने अपने उद्बोधन में कहा कि भाषा ही विचारों की अधिष्ठािका का सारक माध्यम है। किसी भी देश की पहचान उसकी भाषा से होती है। उन्होंने कहा कि सभी शासकीय कार्य हिंदी में किए जाने चाहिए तथा सरकारी कामकाज में देवनागरी हिंदी के प्रयोग को बढ़ावा देना हम सबकी जिम्मेदारी है। विशेष अतिथि खान प्रवेशक विवेक कुमार ने कहा कि नगरास द्वारा विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं, फिर भी इसे और सशक्त बनाने की आवश्यकता है। उन्होंने सभी से अपने कार्यवाहों कार्य अधिकाधिक हिंदी भाषा में करने का आह्वान किया। कमांडेंट श्री कैप्टन गिल ने बैठक को नगरास

का एक सारहवीं प्रयास बताते हुए कहा कि सभी केंद्रीय कार्यवाहों का एक मंच पर आकर हिंदी के सशक्तिकरण के लिए कार्य करना अत्यंत सकारात्मक कदम है। बैठक के दौरान सत्र 2024-25 में राजभाषा नीति के सर्वोत्कृष्ट क्रियान्वयन हेतु विभिन्न केंद्रीय कार्यवाहों को राजभाषा प्रसूतार प्रदान किए गए। इसमें श्रेणी-एक (केंद्रीय अधिशासी संस्थान), श्रेणी-दो (राष्ट्रीयकृत बैंक एवं बीमा कंपनियां) के अंतर्गत ग्राम, द्वितीय एवं तृतीय प्रसूतार से कार्यवाहों की समाप्तित किया गया। बैठक में सहायक निदेशक श्री कुंवर विक्रम सिंह एवं जिला अग्रणी बैंक प्रबंधक श्री सुनील कुमार ने भी राजभाषा की महत्ता एवं कार्यवाहों की भूमिका पर अपने विचार व्यक्त किए। सभी वक्ताओं ने सरकारी कार्यों में हिंदी के प्रयोग को बढ़ाने और इसे व्यवहारिक रूप से लागू करने पर बल दिया।

खापा में मेरा युवा भारत और डिजिटल साक्षरता को लेकर सात दिवसीय शिविर

पद्मेश न्यूज । वाराणसी ।

शासकीय शासकीय शंकर साव पटेल महाविद्यालय में संचालित राष्ट्रीय सेवा योजना इकाई का सात दिवसीय विशेष शिविर ग्राम पंचायत खापा 29 जनवरी 2026 से 8 फरवरी 2026 तक मेरा युवा भारत तथा डिजिटल साक्षरता के लिए युवा विषय पर आयोजित किया गया। शिविर के तृतीय दिवस ग्राम पंचायत खापा के बाईक मार्च 19.12.24 में परियोजना कार्य करने के पश्चात बौद्धिक

करना है तो लक्ष्य निर्धारित करना होगा, हमें मजबूत पक्ष, कमजोर को ध्यान में रखते हुए लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए अवसर को तलाश में होंगे और सही निर्णय लेना होगा। वहीं प्रमिला चौहान ने बताया कि

सत्र के कार्यक्रम में ग्रामीण विकास में युवाओं की भूमिका और जनसंचार माध्यमों का योगदान विषय पर मुख्य अतिथि डॉ. अनिरुद्ध सिंह काकोडिया, विभिन्न अतिथि श्रीमती प्रमिला चौहान प्रधान, प्रकाश कठाने, हर्षिता मेश्राम, शिखा देवीगौरीकर उपस्थित रहे। मुख्य अतिथि के द्वारा ग्रामीण विकास में युवाओं की भूमिका और जनसंचार माध्यमों में युवाओं को बताया कि हमें अगर समाज और ग्राम का विकास

युवा पीढ़ी नए विचारों के साथ सामंजस्य करने एवं परिवर्तन को स्वीकार करने में अग्रणी होते हैं। समाज कल्याण एवं राष्ट्र हित में युवाओं को मध्यस्थता की भूमिका अदा करते देखा गया है। तृतीय दिवस के बौद्धिक कार्यक्रम में मंच संचालन का कार्य गिराना मैश्राम के द्वारा किया गया और अंत में कृष्णा पराते कायकम अधिकारी द्वारा सभी का आभार व्यक्त करते हुए कार्यक्रम का समापन किया गया।



राष्ट्रीय सेवा योजना इकाई रास. शंकर साव पटेल महाविद्यालय वाराणसी, बि. ज. नगर (क.प्र.)

किरानापुर में पेट्रोलपंपों का किया गया निरीक्षण

पद्मेश न्यूज । किरानापुर । जिले में संचालित पेट्रोलपंपों पर शासन द्वारा निर्धारित मापदण्ड के अनुसार सुविधाओं की उपलब्धता सुनिश्चित करने के

आवश्यक सुविधाओं का अवलोकन किया गया। इस दौरान निर्देशित किया गया कि हवा भरने की मशीन चालू हालत में रहना चाहिए और जरूरतमंद व्यक्ति कि निर्देशित किया गया कि हवा भरने की मशीन चालू हालत में रहना चाहिए और जरूरतमंद व्यक्ति कि



लांजी में "पद्मेश"

इंटरनेट (ब्राडबैंड)

कनेक्शन के लिये संपर्क करें

Mo. 8319969927

मप्र के 6 जिलों में बढ़ेगी विकास की रफ्तार

केंद्रीय बजट से भरेगी मप्र की तिजोरी, टैक्स और ग्रांट से मिलेंगे 1,12,133 लाख करोड़
-प्रदेश के 5 लाख से अधिक आबादी वाले शहरों के इंफ्रास्ट्रक्चर विकास के लिए विशेष प्रावधान

भोपाल । केंद्रीय बजट से मप्र के खजाने में टैक्स और ग्रांट से 1,12,133 लाख करोड़ मिलेंगे। वहीं मप्र के भोपाल, इंदौर, सहित करीब आधा दर्जन शहरों के विकास में पंख लगने जा रहे हैं। केन्द्रीय बजट में प्रदेश के इन शहरों सहित प्रदेश की 5 लाख से ज्यादा आबादी वाले शहरों के इंफ्रास्ट्रक्चर को विकसित किया जाएगा। दरअसल, केन्द्रीय बजट में सरकार ने छोटे शहरों को बढ़ावा देने के लिए इंफ्रा फंड का प्रावधान किया है। इसके जरिए 5 लाख से ऊपर आबादी वाले शहरों में सरकार इंफ्रा ब्यूट करेगी। इसके लिए ईका रिकम फंड बनाया जाएगा। इसकी मदद से केंद्र कर्पनीयों को सपोर्ट किया जाएगा। टीएच और टीएच 3 शहर देश की रस्ता की गाँव दे रहे हैं। इन शहरों में आधारभूत संरचना को बढ़ावा देने के लिए 5 लाख से ज्यादा आबादी को नियंत्रित 2 और 3 के शहरों के विकास के लिए 11.2 लाख करोड़ का आवंटन किया गया था, जिसे 2026-27 में बढ़ाकर 12.2 लाख करोड़ किया गया है। इसे शहरों के विकास की रफ्तार को भी कारिंदे बनाया जा रहा है। आगले 5 सालों में हर शहर में करीब 5 हजार करोड़ रुपए खर्च होंगे। इससे मध्य प्रदेश के शहरी इलाकों की भी बढ़ावा देना होगा। मध्य प्रदेश में भोपाल, इंदौर, ग्वाल्थर, जबलपुर, उज्जैन सहित आधा दर्जन से ज्यादा शहरों को जसजसा 5 लाख से अधिक है। इसके अलावा इन शहरों में विकास की रफ्तार बढ़ेगी।

गौरतलब है कि पिछले कुछ वर्षों में केंद्रीय बजट में मप्र का हिस्सा तेजी से बढ़ा है। जहाँ 2017-18 में यह करीब 51



हजार करोड़ रुपये था, वहीं 2024-25 में यह बढ़कर एक लाख करोड़ रुपये के पार पहुँच गया। 2026-27 के बजट अनुमानों में यह अंकाज पहले 1,11,662 करोड़ रुपये तक जाने का संकेत दे रहा था। अब केंद्रीय बजट पेश होने के बाद मप्र के खजाने में टैक्स और ग्रांट से 1,12,133 लाख करोड़ मिलेंगे। बजट में 5 लाख से अधिक आबादी वाले शहरों के विकास के लिए 5000 करोड़ रुपये का आवंटन किया गया है। प्रत्येक जिले में महिला छात्रावास का निर्माण और जिला अस्पतालों का अपग्रेडेशन मध्य प्रदेश के सामाजिक ढाँचे को मजबूत करेगा। कृषि के क्षेत्र में पीएम धन-धान्य कृषि योजना से राज्य के कम उपलब्धता वाले जिलों में सिंचाई और भंडारण सुविधाओं में व्यापक सुधार होगा।

मप्र के हिस्से में 2,785 करोड़ का इंफ्राफंड
मप्र में डबल इंजन की सरकार होने

के माध्यम से होती है। जोएसटी लागू होने के बाद से राज्यों के पास कर यानी टैक्स लगाने के अवसर सीमित हो गए हैं, इसलिए केंद्रीय बजट में हिस्से की भूमिका बढ़ गई है। यह प्रदेश को 7.34 प्रतिशत के हिसाब से मिलेगा। केंद्रीय सहायता अनुदान 48,661 करोड़ रुपये में भी कमी की संभावना है। यह केंद्र प्रवर्तित योजनाओं में केंद्रों के हिसाब से 47 हजार करोड़ रुपये के आसपास रह सकता है। राज्य के ऊपर इसका वित्तीय भार अवश्य पड़ेगा क्योंकि विकास भार तीन-राम-तीन में राज्य को अब 30 प्रतिशत अधिक भारों को व्यवस्था करनी होगी।

वर्देरी और महेश्वर को मिलेगा वैश्विक मंत्र
बजट में टेक्स्टाइल क्षेत्र के सुधारों पर विशेष ध्यान दिया गया है। विलेज मोड के तहत मेगा टेक्स्टाइल पार्क की घोषणा से मध्य प्रदेश के पारंपरिक क्लस्टर जैसे चंदेरी, महेश्वर और बुलढापुर में तकनीकी उद्यम होगा। सामर्थ्य-2 योजना के माध्यम से राज्य के युवाओं को व्यावसायिक विनिर्माण का प्रशिक्षण मिलेगा, जबकि महामा गांधी ग्राम स्तर पर पहल खादी और हस्तशिल्प से जुड़े जिलों में युवाओं को सीधा रोजगार और वैश्विक बाजार उपलब्ध करायी है।

वाइब्रेंट कल्चरल डेस्टिनेशन बनेगा एमपी
मध्य प्रदेश के ऐतिहासिक और पुरातात्विक स्थलों जैसे खजुराहो और भंडावाट को वाइब्रेंट कल्चरल डेस्टिनेशन

के रूप में विकसित किया जाएगा। बजट में नेशनल हॉस्पिटैलिटी संस्थान और गाइडों के लिए पावेलट प्रोजेक्ट का प्रावधान है, जो स्थानीय स्तर पर रोजगार सृजित करेगा। साथ ही, कारा और बांधवगढ़ जैसे राष्ट्रीय उद्यानों में बड़े वाणिज्य और माउंटन ट्रेल्स के विकास से इको-टूरिज्म को नई गति मिलेगी।

भारत का डेटा रेट वल बनने की डेटा स्टोर

मध्य प्रदेश की केंद्रीय भौगोलिक स्थिति इसे डेटा केंद्रों के लिए आदर्श बनाती है। बजट में विदेशी डेटा कंपनियों के लिए टैक्स हॉलीडू की घोषणा राज्य के लिए गैर-चेंजर सावित हो सकती है। इससे एआई और क्लाउड कंप्यूटिंग के निष्पादों ढांचे में सुधार होगा और युवाओं के लिए हाई-टेक नौकरियों के अवसर पैदा होंगे। इलेक्ट्रॉनिक्स वित्तियोग क्लस्टर और रोबोटिक्स में सहयोग से मध्य प्रदेश तकनीक के क्षेत्र में अग्रणी बनेगा।

10,000 करोड़ का बड़ा निवेश
देश में बायो-फार्मा वित्तियोग के लिए 10,000 करोड़ रुपये के प्रावधान से मध्य प्रदेश का फार्मा सेक्टर नई ऊँचाईयों को छुएगा। राज्य में माँझूर फार्मा हब को उन्नत किया जा रहा है और क्लीनिकल ट्रायल साइटों के नेटवर्क से चिकित्सा अनुसंधान को बढ़ावा मिलेगा। इसके अतिरिक्त, 200 पुराने औद्योगिक क्लस्टरों को पुनर्जीवित करने की योजना से पुराने औद्योगिक क्षेत्रों का आधुनिकीकरण होगा।

सरकार लोगों को जहरीला पानी पिला रही है

राज्यसभा में उठा इंदौर में दूषित पानी से मौत का मामला, कांग्रेस के प्रमोद तिवारी ने कहा
भोपाल । इंदौर के केबिनेट मंत्री उठिए, मोर्चा संभालिए। मैं जानना चाहता हूँ कि विश्व की मानवता से जुड़ा हुआ, हर इंसान से जुड़ा एक महत्वपूर्ण सवाल राज्यसभा में उठाते हुए कहा है कि पानी सबसे गोमौर विषय है और जहरीला पानी सरकार पिला रही है, इंदौर कोई दो पत्र नहीं है, तिवारी ने कहा कि इस विषय में जितना करण है, शायद किसी और विषय में उतना करण नहीं है। इसलिए हम पर गोमौर से विचार होना चाहिए। उन्होंने केंद्रीय मंत्री से आग्रह किया कि इसकी कार्ययोजना से अग्रगत करे।



है। क्या सदन को आश्चर्य करेगा कि जो ग्राउंड वाटर है, उसकी क्वालिटी बेहतर करने के लिए क्या कार्ययोजना आगे पानी है। **तया केंद्र ने राज्य से खाल किया, रिपोर्ट मांगी**
राज्यसभा में महाराष्ट्र राज्यसभा सदस्य इमरान प्रतापगढ़ी ने कहा कि मध्य प्रदेश के इंदौर में दूषित पानी पीने से 30 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। इसलिए वे विभागीय मंत्रियों से पूछना चाहते हैं कि इन मौतों का जिम्मेदार

किसको माना जा रहा है? क्या इंदौर में सिर्फ राज्य सरकार की जिम्मेदारी है? क्या जल शक्ति मंत्रालय ने इसमें संज्ञा लेते हुए राज्य सरकार से सवाल किया? क्या इस मामले में राज्य सरकार ने कोई रिपोर्ट प्रस्तुत की? इसकी जानकारी दी जाए।

सांसद डॉ. रमेश नाथिर हुदैन ने दूषित पानी पूछे थे

इससे पहले कर्नाटक से राज्यसभा सांसद और कांग्रेस नेता डॉ. रमेश नाथिर हुदैन ने राज्यसभा में इंदौर के खतरनाक और जल आपूर्ति सिस्टम को लेकर सरकार से सीधे सवाल पूछे थे।

इंदौर में दूषित पानी से अब 32 लोगों की मौत

भागीरथपुर में दूषित पानी पीने से मौतों का सिलसिला जारी है। आज भी एक व्यक्ति की मौत अस्पताल में इलाज के दौरान हो गई है। इंदौर में दूषित पानी से मौत का आंकड़ा अब 32 तक पहुँच गया है।

मंदसौर पुलिस की अवैध मादक पदार्थों के विरुद्ध बड़ी कार्रवाई

भोपाल । प्रदेश में नशे के अंधे कालों के विरुद्ध मध्यप्रदेश पुलिस द्वारा लगातार सख्त एवं प्रभावी कार्रवाई की जा रही है। इसी क्रम में मंदसौर जिले की थाना सिटी कोतवाली पुलिस ने लगभग 1 करोड़ 50 लाख रूपय से अधिक की एमडी ड्रग्स के साथ दो आरोपियों को गिरफ्तार किया है। यह कार्रवाई पुलिस अधीक्षक मंदसौर श्री विनोद कुमार मोना के मार्गदर्शन में अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक मंदसौर श्री जितेंद्र सिंह भास्कर के निदेशन में थाना प्रभारी कोतवाली श्री पुष्पेन्द्र सिंह ठाकुर के नेतृत्व में की गई।

01 फरवरी को थाना कोतवाली को मुखबिर से सूचना प्राप्त हुई कि देवलजी, जिला प्रतापगढ़ (राजस्थान) निवासी गुलशेर खान पटना एमडी ड्रग्स के कार्रवाई उर्फ नंदु को बेचना मंजूर करा रहा है। सूचना पर थाना कोतवाली पुलिस ने मुखबिर के बताने रचना पर कार्रवाई करते हुए गुलशेर खान पटना एवं उसके साथ भीषण नर्दीक्षिकी उर्फ नंदु को पकड़ दबाया। तत्पश्चात् की दौरान दोनों आरोपियों के कब्जे से 01 किग्रा 500 ग्राम अवैध पदार्थ ड्रग्स, जिसकी अंतरालीय मात्रा में अनुमानित कीमत 1 करोड़ 50 लाख है, बचपक की गई। इसके अतिरिक्त 7,000 कीमत का अवैध डेडस्टॉक तथा पटना में प्रचुड़ दो मोटरसाइकिल भी जब्त की गई।

जामवाल ही संभालेंगे प्रदेश भाजपा संगठन की कमान

भोपाल । मध्यप्रदेश भाजपा संगठन की पिछले चार वर्षों से कमान संभाल रहे हिनांदन को संगठन महामंत्री के पद से हटाने के बाद अब अगले प्रदेश संगठन महामंत्री के नाम को लेकर राजनीतिक विश्लेषक बकास लगा रहे हैं। हालाँकि सच इस बार में कोई विचार नहीं कर रहा है। इसके पीछे जो कारण बताए जा रहे हैं। वह भी काफी चीजें बताते हैं।

हिनांदन को प्रदेश सह वीरध्वज प्रमुख बनाए जाने के साथ ही प्रदेश संगठन महामंत्री का काम क्षेत्रीय संगठन महामंत्री अजय जामवाल को दे दिया गया है। लेकिन जामवाल इस जवाबदाारी को किनेते दिन भालेंगे यह भी चर्चा का विषय बना हुआ है। माना जा रहा है कि संघ ने अगले प्रदेश संगठन महामंत्री का नाम को लेकर नाम तय कर लिया है लेकिन अभी घोषणा नहीं की जाएगी। इसके पीछे जो कारण बताए जा रहे हैं वह यह है कि अगर अजय जामवाल

संघ नए प्रदेश संगठन महामंत्री को लेकर पड़ोसी राज्यों के नेताओं में कर रहा तलाश

इस पद का दायित्व पूर्ण रूप से संभालने के लिए तैयार हो जाते हैं तो संघ उन्हें ही दो जालिय सीप सकता है।

- संघ नया प्रयोग करने के प्रयास में

इसके अलावा संघ यह भी सोच कर चल रहा है कि अगर प्रदेश में संगठन महामंत्री के पद की जरूरत नहीं हुई तो फिर इस पद पर किसी को नहीं लाया जाएगा। इसके पीछे जो कारण बताए जा रहे हैं वह यह है कि पिछले करीब चार-पांच वर्षों से राजस्थान में भी पटना महामंत्री का पद खाली है और ऐसे में भाजपा ने दो वर्ष पूर्व सता में वापसी की है। ऐसे में माना जा रहा है कि यदि संघ को जामवाल है कि मध्यप्रदेश की भी भाजपा को प्रदेश संगठन महामंत्री के बरबर चुनाव जा सकता है। तो फिर नव व्यक्ति को इस पद पर लाने से कोई फायदा नहीं होगा।

महिने के अंत तक सभी जिलों की कार्यकारिणी का हो जाएगा गठन

मप्र कांग्रेस में जिला कार्यकारिणी का गठन शुरू
भोपाल । मिशन-2028 की तैयारियों में जुटी मप्र कांग्रेस कमेटी ने पहले इंतजार के बाद जिला कार्यकारिणी का गठन शुरू कर दिया है। पार्टी दो दिन में चार जिलों-सागर, छिंदवाड़ा, मऊजगढ़ व झाबुआ की कार्यकारिणी घोषित कर चुकी है। अने वाले दिनों में चरणबद्ध तरीके से अन्य जिलों की कार्यकारिणी घोषित की जाएगी। कोशिश है कि फरवरी अंत तक सभी 71 जिलों की कार्यकारिणी घोषित कर दी जाए। हालाँकि यह किसी चुनौती से कम नहीं है। वरिष्ठ कांग्रेस नेताओं का कहना है कि अधिकतर जिला कार्यकारिणी के नाम पसंदन हो चुके हैं। उनकी औपचारिक घोषणा होना बाकी है। कुछ जिलों की कार्यकारिणी के नामों पर संघन सख्त रहा है। कार्यकारिणी के साथ ही पार्टी करीब 250 ब्लॉक अर्थशर्षों की नियुक्ति की तैयारी में है। अने तक 800 से ज्यादा ब्लॉक अर्थशर्षों की नियुक्तियों का जो चुकी है, लेकिन दिनालधस होने पांच माह बीत जाने के बाद भी जिला कार्यकारिणी की घोषणा नहीं किए जाने से स्थानीय नेताओं में असंतोष पैदा होने लगा है। विधायकों तथा प्रत्यक्ष अंग संधिार ने मप्र कांग्रेस के गठन में देरी को लेकर भोपाल में मीडिया से चर्चा में कहा था कि जितनी जल्दी संगठन मजबूत ढाँचे में बदलेगा, उतनी ही बेहतर चुनावी तैयारी होगी। हम जितनी जल्दी संगठन बनाएँगे, उतनी ही मजबूती से चुनाव की तैयारी कर पाएँगे। इसलिए तनित बार शुक्रवार को पीसीसी ने तीन जिला कार्यकारिणी और 18 जिला संगठन महामंत्रियों की घोषणा कर दी। मध्य प्रदेश कांग्रेस के संगठन महामंत्रियों डॉ. संजय काकना का कहना है कि संगठन के गठन की प्रक्रिया तेजी से जारी है। जिला, ब्लॉक, पंचायत एवं वार्ड स्तर पर अंतर्गत की जा रही है। हमारी कोशिश है कि जल्द से जल्द संगठन के गठन का काम पूरा कर लिया जाए, ताकि पूरी ताकत से आगामी विधानसभा चुनाव की तैयारियों में जुटा जा सके।

आईपीएस अफसरों पर बढ़ा प्रतिनियुक्ति का दबाव

नियमों में हुए बदलाव, 2011 और बाद के अधिकांशों पर पड़ेगा असर

भोपाल । केंद्र सरकार द्वारा आईपीएस अधिकारियों के एम्पेनलमेंट नियमों में किए गए बदलाव के बाद मप्र के डेढ़ के आधीएस अफसरों पर केंद्रीय प्रतिनियुक्ति पर जाने का बड़ा दबाव बना गया है। नए नियमानुसार 2011 बैच और उसके बाद के आईपीएस अधिकारियों को केंद्र सरकार में आईजी स्तर पर एम्पेनलमेंट पाने से पहले एसपी या डीआईजी रैंक पर कम से कम दो साल की केंद्रीय प्रतिनियुक्ति अनिवार्य रूप से पूरी करनी होगी।

इस फैसले को केंद्र की उस नीति की अगली कड़ी के तौर पर देखा जा रहा है, जिसके तहत करीब चार महीने पहले केंद्र सरकार ने मध्य प्रदेश सरकार को मप्र बेजकर आईपीएस अधिकारियों को केंद्रीय प्रतिनियुक्ति पर भेजने को लेकर पुलिस मुख्यालय को कहा था। उस पत्र में स्पष्ट रूप से कहा गया था कि केंद्र के अधीन विभिन्न विभागों और केंद्रीय पुलिस संगठनों में एसपी और डीआईजी स्तर पर अधिकारियों की कमी है और राज्यों से पर्याप्त संख्या में अफसर उपलब्ध नहीं कराए जा रहे हैं।

आईपीएस को दो साल का डेयुटीशन जरूरी

अब नए एम्पेनलमेंट नियम लागू होने के बाद वह पत्र एक तरह से अनिवार्यता में बदल गया है। मप्र के डेढ़ के वे आईपीएस अधिकारी, जिनकी अब तक केंद्रीय प्रतिनियुक्ति नहीं ली है, उनके लिए भविष्य में केंद्र में सेवा देना लगभग अनिवार्य सा हो गया है। यदि वे आगे चलकर केंद्र सरकार में आईजी स्तर के लिए एम्पेनलमेंट होना चाहते हैं, तो उन्हें वह अवधि तक कम से कम दो साल के लिए केंद्रीय प्रतिनियुक्ति पर जाना ही होगा।

इन अफसरों को जाना होगा छिछो

मप्र के डेढ़ के 2011 बैच के रियाज इकबाल, राहुल लोढ़ा, मिमाला प्रसाद और डॉ. अमित वादय तथा 2012 बैच के मयंक अस्थवी, विवेक सिंह, कुमार प्रतीक, शिव दयाल और शैलेन्द्र सिंह चौहान ऐसे अधिकारी हैं, जो अब तक केंद्रीय प्रतिनियुक्ति पर नहीं गए हैं। वे सभी अफसर अब डीआईजी हो गए हैं, इन अफसरों की अब तीन-चार साल के भीतर केंद्रीय प्रतिनियुक्ति पर जाना होगा। नियमानुसार डीआईजी स्तर पर आईपीएस अफसर को चार साल की सेवाएँ देनी होती हैं। ऐसे में वर्ष 2011 के बैच के अफसरों के पास अब तीन साल का समय है, जबकि 2012 बैच के अफसरों के पास चार साल का समय है। इसके बाद के बैच के अफसरों के पास चार साल से ज्यादा का समय है, जिसमें वे केंद्र में जाने का निर्णय ले सकते हैं।

एसपीएस से आईपीएस की संख्या ज्यादा

ऐसा माना जा रहा है कि इस फैसले का उद्देश्य केंद्रीय पुलिस संगठनों और मंत्रालयों में एसपी और डीआईजी स्तर पर लंबे समय से खाली पड़े पदों को भरना है।

राज्यसभा के लिए भाजपा नेताओं रामप्रकाश वंशकार और डॉ.

अभिजीत देशममुख की दावेदारी

अप्रील में मध्यप्रदेश से खाली होने वाली है 3 सीटें

भोपाल । मध्यप्रदेश भाजपा में राज्यसभा के लिए आगामी अप्रील माह में रिक्त होने वाली 3 सीटों के लिए नेताओं ने दावेदारी शुरू कर दी है। इसके लिए दावेदारों के पक्ष में उनके समाज ने पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष से लेकर प्रदेश अध्यक्ष, मुख्यमंत्री से लेकर संगठन महामंत्री को पत्र भी लिखा।

मप्र से राज्यसभा के तीन सदस्यों कांग्रेस से दिग्विजय सिंह, भाजपा से केन्द्रीय मंत्री जाल कृतिवर्ण एवं प्रदेश महामंत्री डॉ सुमेर सिंह सोलंकी का कार्यकाल समाप्त हो रहा है। इसके लिए भाजपा नेताओं ने अपनी अपनी दावेदारी शुरू कर दी है।

बसौर वंशकार समाज ने पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष से लेकर प्रादेश अध्यक्ष एवं मुख्यमंत्री को पत्र लिख कर राज्यसभा के लिए अनुसूचित जाति मोर्चा के प्रदेश उपअध्यक्ष एवं कार्यालय प्रभारी रह चुके रामप्रकाश वंशकार को टिकट दिए जाने की मांग की है। जिसमें वंशकार के द्वारा पिछले 30 वर्षों से पार्टी संगठन में किए गए कामों के बारे में बताया गया है वंशकार समाज ने अपने पत्र में लिखा है देश की आजादी के बाद से अनुसूचित जाति की सभी जातियों के लोगों को अवसर दिया गया है लेकिन उनके समाज से अभी तक न तो किसी को विचारक बनाया है और न ही सांसद। इसलिए समाज पार्टी मांग कर रह है कि नेता रामप्रकाश वंशकार को राज्यसभा भेज जाए।

इसी तरह भाजपा के एक और नेता डॉ. अभिजीत देशमुख भी राज्यसभा के लिए दावेदारी कर रहे हैं। वह वर्तमान में भाजपा चिकित्सा प्रोफेक्टर के प्रदेश उपअध्यक्ष होने के साथ ही आरोग्य भूरी के जिला संयोजक हैं। देशमुख संघ के करीबी हैं। इस नाने की दावेदारी भी मजबूत मानी जा रही है। अगर राज्यसभा के लिए संघ की बात पर पार्टी टिकट देता है तो देशमुख को टिकट मिलना आसान हो जाएगा।

समाधान योजना के प्रथम चरण में 05 लाख

26 हजार से अधिक उपभोक्ताओं ने लिया सौ

फीसदी तक सरचार्ज में छूट का लाभ

दूसरा चरण शुरू, 28 फरवरी तक एकमुश्तक जमा करने पर सरचार्ज में मिलेगी 90 प्रतिशत छूट

भोपाल । मध्य प्रदेश सरकार की समाधान योजना 2025-26 के प्रथम चरण में 31 जनवरी 2026 तक 5 लाख 25 हजार से अधिक बकायादार उपभोक्ताओं ने सौ फीसदी तक सरचार्ज में छूट का लाभ उठाया है। 01 फरवरी से द्वितीय चरण की शुरुआत हो चुकी है जो कि 28 फरवरी तक चलेगा। मध्य प्रदेश विद्युत वितरण कंपनी ने कहा है कि पिछले साल 3 नवंबर से शुरू हुई समाधान योजना 2025-26 में शामिल होकर लाखों बकायादार उपभोक्ताओं ने सौ फीसदी तक छूट का लाभ लिया। कंपनी ने उपभोक्ताओं से अपील की है कि तनित माह से अधिक के बकायादार उपभोक्ता योजना के प्रथम चरण में शामिल नहीं हो जाए वे अब द्वितीय चरण में शामिल होकर अपना बकाया बिल एकमुश्त जमा करके छूट के साथ एकमुश्तक जमा करके सौ फीसदी तक सरचार्ज माफी का लाभ उठा सकते हैं। मध्य प्रदेश सरकार की समाधान योजना 2025-26 के प्रथम

चरण में मध्य प्रदेश विद्युत वितरण कंपनी के 5 लाख 26 हजार 412 बकायादार उपभोक्ताओं ने अपना पंचवार करण लाभ लिया है। मध्य प्रदेश विद्युत वितरण कंपनी के खाली में 533 करोड़ 14 लाख से अधिक की मूल राशि जमा हुई है, जबकि 263 करोड़ 84 लाख रूपय का सरचार्ज माफ किया गया है।

मध्य प्रदेश सरकार की समाधान योजना 2025-26 के लागू होने से ऐसे अनेक उपभोक्ता हैं जो बकाया बिल जमा कर रहे हैं और एकमुश्त बकाया राशि जमा करने पर अधिकतम छूट का लाभ ले रहे हैं। यह योजना उन बकायादार उपभोक्ताओं के लिए वरदान बनी है जो सरचार्ज के कारण प्लूमर राशि जमा नहीं कर पाए हैं। अब उन्हें समाधान योजना के द्वितीय चरण में सरचार्ज में 50 से लेकर 90 प्रतिशत तक छूट के साथ एकमुश्तक जमा करके सौ फीसदी तक सरचार्ज माफी का लाभ उठा सकते हैं।

मध्य प्रदेश सरकार की समाधान योजना 2025-26 के प्रथम

शिक्षक वर्ग-3 की भर्ती परीक्षा का परिणाम जारी नहीं होने से अभ्यर्थी परेशान

भोपाल । मध्य प्रदेश कर्मचारी चयन मंडल (ईएसबी) द्वारा आयोजित प्राथमिक शिक्षक (वर्ग-3) की चयन परीक्षा-2025 और आबकारी आरक्षक भर्ती-2024 के परिणाम घोषित नहीं होने से हजारों अभ्यर्थी परेशान हो रहे हैं। वर्ग-3 की परीक्षा को चार माह से अधिक समय बीत जाने के बावजूद परिणाम जारी न होने से अभ्यर्थियों में निराशा बढ़ रही है। प्राथमिक शिक्षक चयन परीक्षा-2025 का आयोजन जून से 13 अक्टूबर 2025 के बीच किया गया है। इस परीक्षा के माध्यम से 13,129 पदों पर भर्ती होनी है, जिसके लिए कुल 1,10,745 अभ्यर्थियों ने आवेदन किया था। अभ्यर्थी अपने शर्मा का फेसल है कि परिणाम में तो देरी देरी से ही परीक्षा प्रक्रिया प्रभावित होगी। काउंसिलिंग, दस्तावेज सत्यापन और अंतिम निष्पत्ती में आदेशबद्ध विवरण की आधारता बढ़ गई है। उम्मीद है कि मध्यमिक व प्राथमिक शिक्षक पाठाना परीक्षा की जुलाई-अगस्त में होगी। वर्ग-3 के अभ्यर्थी समाचार को अपनी मांग को लेकर भोपाल में प्रदर्शन कर रहे हैं।

अस्थक भर्ती का परिणाम जारी

अभ्यर्थी की कल खजुरिया ने कहा कहना है कि प्राथमिक शिक्षक परीक्षा के बाद आबकारी पुलिस आरक्षक भर्ती-2025 के प्रथम चरण के परिणाम 25 जनवरी को घोषित कर दिया जाए। पुलिस आरक्षक भर्ती परीक्षा 30 अक्टूबर से 15 दिसंबर 2025 के बीच आयोजित हुई थी। ऐसे में अभ्यर्थियों का कहना है कि जब तक वे नहीं पूर्ण परीक्षा परिणाम जारी किया जा सकता है, तो पहले आयोजित प्राथमिक शिक्षक भर्ती का रिजल्ट जारी किया जाए।

